

प्रेषक,

डी०एस० गब्याल,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।
4. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।

वित्त(वे०आ०-सा०नि०)अनुभाग-7

देहरादून: दिनांक: 27 अक्टूबर, 2016

विषय:- अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2015-2016 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान।

महोदय,

उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अन्तर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में शासनादेश संख्या-212/XXVII(7)बोनस/2012-15 दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 द्वारा अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, कैजुअल एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2014-2015 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किये गये थे।

2- भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सेवा के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 द्वारा वर्ष 2015-2016 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैं।

3- उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 के क्रम में राज्य सरकार के समस्त पूर्णकालिक राज्य कर्मचारियों राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों जिनके द्वारा धारित पद का अधिकतम ग्रेड वेतन रु० 4800/- (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित वेतनमानों में जिनका वेतनमान का अधिकतम रु० 13,500/- से कम है) में है तथा जो अराजपत्रित श्रेणी में हों, को वर्ष 2015-2016 के लिए 30 दिन

11

की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. नई वेतन संरचना के अन्तर्गत ग्रेड वेतन 4800/- तक के पद (पूर्व में अपुनरीक्षित वेतनमानों में जिनके वेतनमान का अधिकतम रु0 13,500/- से कम है) में कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों, जिन्हें उपरोक्त ग्रेड वेतन/वेतनमान से उच्च ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान, समयमान वेतनमान अथवा वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ हो और उनकी प्रास्थिति (स्टेटस) में कोई परिवर्तन न हुआ हो, को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा।
2. इन आदेशों के अन्तर्गत केवल वही अराजपत्रित कर्मचारी बोनस सुविधा हेतु पात्र होंगे, जो दिनांक: 31 मार्च, 2016 को राज्य सरकार की नियमित सेवा में थे और जिन्होंने 31 मार्च, 2016 तक न्यूनतम छः माह की लगातार सेवा पूर्ण कर ली हो। वर्ष के दौरान न्यूनतम छः महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक अदायगी स्वीकार्य होगी, पात्रता अवधि की गणना सेवा के महीने (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित) की संख्या में की जायेगी।
3. तदर्थ बोनस के लिए एक माह में औसत दिनों की संख्या-30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2016 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ आगणित की जायेगी।
4. दिनांक 31 मार्च, 2016 वास्तविक परिलब्धियाँ रु0 7000/- से ज्यादा ज्यादा होने की स्थिति में रु0 7000/- की परिलब्धि मानकर 31 मार्च, 2016 को 30 दिन की परिलब्धियों (रु0 7000X30/30.4=6907.89 अर्थात 6908/-) तदर्थ बोनस के रूप में अनुमन्य होगी। तदर्थ बोनस की आगणित धनराशि को निकटतम एक रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा।
5. ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में अपराधिक मुकदमा लम्बित हो, को तदर्थ बोनस का भुगतान, ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमे का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को वर्ष 2015-16 में किसी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा आपराधिक मुकदमे में दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय नहीं होगा।
6. किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ बोनस के सम्बन्ध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात आगामी वर्षों में किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।

4- कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2016 को 03 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2016 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है, परन्तु उक्त तिथि तक कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों

अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष 240 दिन कार्यरत रहे हो, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में संबंधित कर्मचारी के लिए मासिक परिलब्धियां रु0 1200 प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ बोनस की देय धनराशि $\text{रु}01200 \times 30 / 30.4 = 1184.21$ अर्थात् रु0 1184/- (पूर्णांकित) होगी। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियां रु0 1200 प्रतिमाह से कम हैं उन्हें तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आंकलित की जायेगी।

5- अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद में किया जायेगा।

6- बोनस के भुगतान से संबंधित शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-120/दस-1(एम)/84, दिनांक 18 जनवरी, 1984 के प्रस्तर-1(7), 5 तथा 6 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्ध इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के विषय में भी यथावत लागू रहेंगे।

7- उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय-व्ययक के उसी लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा जिससे संबंधित कर्मचारियों के वेतन व्यय को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद "वेतन" के अंतर्गत पुस्तान्कित किया जायेगा।

भवदीय,

(डी0एस0 गार्बाल)
सचिव।

संख्या: (1)/XXVII(7)बोनस/2012-16 एवं तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग/शहरी विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि आपके अधीनस्थ निकाय/उपक्रमों में यदि बोनस की देयता हो और सम्बन्धित निकाय/उपक्रम उक्त व्ययभार को वहन करने में सक्षम हो तो कृपया अपने स्तर से उक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रमों में नियुक्ति कार्मिकों को तदर्थ बोनस अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय लेते हुये आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में पुनः वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।

7. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं-261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।
8. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
12. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
13. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस शासनादेश की 100 प्रतियाँ मुद्रित कर वित्त विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
14. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को उत्तराखण्ड राज्य वेब पोर्टल में अपलोड करने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)
अनु सचिव।